

ग्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I-- खण्ड 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं ः 100

नई दिल्ली, शकवार, जन 5, 1970/ज्ये व्ह 15, 1892

No. 100)

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 1970/JYAISTHA 15, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह मलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in ord r that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

RESOLUTION

New Delhi, the 4th June 1970

- No. F. 7(25)-E.III(A)/69.—The Government of India have decided to make the following amendments to the Resolution No. F 7(25)-E.III(A)/69 dated the 23rd April 1970, setting up the Pay Commission
- 2. For the existing sub-para (vii) of para 2, the following shall be substituted namely:—
 - (vii) having regard to all relevant factors, the Commission may, while enquiring into the level of minimum remuneration, examine the Central Government employees' demand for a need-based minimum wage, which is based on the recommendations of the 15th Indian Labour Conference.
 - 3. For the existing para 4, the following shall be substituted, namely:—
 - 4. In case the need for consideration of relief of an interim character arises during the course of deliberations of the Commission, the Commission may consider the demand for relief of an interim character and send reports thereon. In the event of the Commission recommending any interim relief, the date from which this relief

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/Administrations of Union Territories and all other concerned.

P. GOVINDAN NAIR, Secy.

बिक्त संज्ञाल ।

सं कल्प

नई दिल्ली, 4 जून, 1970

सं० फा० 7(25)—ई III $(\mathbf{v})/69$.—वेतन प्रायोग की निमुक्ति से सम्बन्धित, 23 प्रप्रैल 1970 के संकल्प सं० फा० 7(25)—ई $III(\mathbf{v})/69$ में भारत सरकार ने निम्नलिखित संगोधन करने का निर्णय किया है ;

- 2: पैंशाग्राफ 2 के त्रिधमान उप-पैराग्राफ (\mathbf{V}^{ij}) के स्थान पर निम्नलिखिन प्रतिस्थापित किया जायगा:——
 - (Vii) त्यूनतम पारिश्रमिक स्तर सम्बन्धी जांच करते समय, मभी संगत तथ्य को ध्यान में रखते हुए, श्रायोग, केन्द्रीय संरक्षार के कर्मचारियों की, श्रावश्यकता पर श्राधारित न्यूनतम वेतन की मांग की जांच कर मकता है, जो 15वे भारतीय अस सम्मेलन की सिफारिशों पर श्राधारित है।
 - विद्यमान पैराग्राफ 4 के स्थान पर निम्निलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :---
 - 4. भायोग के विचार विमर्ग के दौरान यदि अन्तरिम किस्म की राहत पर विचार करने की भ्रावश्यकता महसूस की जाय तो भायोग भन्तरिम किस्म की राहत की मांग पर विचार कर सकता है और उस पर रिपोर्ट भेज सकता है। यदि श्रायोग किसी भन्तरिम राहत की सिफारिश करे तो वह यह सुझाव भी देगा कि उक्त राहत किस तारीख से दी जाय।

श्रादेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपक्र में प्रकाशित किया जाय । यह श्रादेश भी दिया जाता है कि इस संपत्त्य की प्रतिलिपि भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागां, राज्य सरकारों/संव राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों श्रीर श्रम्य सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जांय ।

> पी० गोविन्दन् नायर, स<mark>चित्र, भा</mark>रत सरकार ।